LOK SABHA

Monday, July 25, 1977/Sravana 3, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: A very bad precedent has been set up. This is very bad. Will you please permit me, Sir?

MR. SPEAKER: No, please. After Question Hour. Shri Ishwar Choudhary.

विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना

*605. **श्री ईश्वर चौधरी**: क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है और उन्होंने कब से क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं सहित निम्नलिखित 84 विश्वविद्यालयों 1-7-1976 को निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे है :—

1. आगरा
2. अलीगढ़ मुस्लिम
3. इलाहाबाद
4. आन्ध्र
5. अन्नामले
6. अवध
7. अवधेश प्रताप सिंह
8. बनारस हिन्दू
9. बंगलौर
10. भोपाल
11. भागलपुर
12. बिहार
13. बम्बई
14. बुन्देलखण्ड
25. वर्दवान
16. कलकत्ता
17. कालीकट
18. कोचीन
19. दिल्ली
20. डिब्रूगढ़
21. गोहाटी
22. गढ़वाल

23. जी०बी० पन्त
24. गोरखपुर
25. गुजरात
26. गुजरात कृषि
27. गुजरात आयुर्वेद
28. गुरू नानक देव
29. हरियाणा कृषि
30. हिमाचल प्रदेश
31. इन्दिरा कला संगीत
32. इन्दौर
33. यादवपुर
34. जबलपुर
35. जम्मू
36. जवाहर लाल नेहरू
37. जे० एम० कृषि
38. जीवाजी
39. जोधपुर
40. कानपुर
41. कल्याणी
42. के०एस० दरभंगा
43. कर्नाटक
44. काशी विद्यापीठ
45. काश्मीर
46. केरल
47. कुमायूं
48. कुरूक्षेत्र
49. लखनऊ
50. ललित नारायण मिथिला
51. मद्रास
52. मदुरै
53. मगध
54. महाराजा सयाजीराव
55. मराठवाड़ा
56. मेरठ
57. उस्मानिया
58. मैसूर
59. उत्तर बंगाल
60. पंजाब
61. नागपुर
62. पटना
63. पूना
64. पंजाबी
65. रविंद्र भारती
66. राजस्थान
67. राजेन्द्र कृषि
68. रांची
69. रवि शंकर
70. सम्बलपुर
71. सम्पूर्णानन्द संस्कृत
72. सरदार पटेल
73. सागर
74. सौराष्ट्र
75. शिवाजी
76. एस०एन०डी०टी० महिला
77. दक्षिण गुजरात
78. श्री वेंकटेश्वर
79. उदयपुर
80. विक्रम
81. विश्व भारती
*82. गुजरात विद्यापीठ
*83. गुरुकुल कांगड़ी
*84. जामिया मिलिया इस्लामिया

---

* विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाएं ।

2. इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को लागू करने के कार्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री ईश्वर चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिन विश्वविद्यालयों में गांव की या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उन में किस विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है इस का उल्लेख नहीं है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय को मद्देनजर रखते हुए उन क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं, क्या इस सम्बन्ध में आचार्य, प्राचार्य लोगों की व्यवस्था कर दी गई है? यदि नहीं, तो इसे करने में कितना समय लगेगा?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रश्न के उत्तर में विश्वविद्यालयों के नाम दिये गये हैं, लेकिन कब से और कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होती है इस समय वह मैं नहीं जानता हूं और न ही प्रश्न में था कि कौन सी भाषाओं में वहां पढ़ाया जाता है।

दूसरा जो सवाल माननीय सदस्य का है उसके बारे में मेरा कहना है कि टैक्स्ट बुक्स बनाने के लिये अनुदान केन्द्रीय सरकार की ओर से दिया जा रहा है। चौथी योजना काल में 6 करोड़ रुपये दिए गए और पांचवीं योजना काल में 7 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिये राज्य सरकार ने कुछ कमेटियां बनायीं हैं जो पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही हैं। इनमें से 4300 किताबें तमाम भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिये जगह-जगह अध्यापक भी हैं।

श्री ईश्वर चौधरी: मैंने स्पष्ट पूछा है कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये क्या उचित व्यवस्था कर ली है, पुस्तकें जितने रूप में छपनी चाहियें नहीं छपी हैं और जितने शिक्षक रहने चाहियें, आचार्य, प्राचार्य, वह भी नहीं है, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समुचित व्यवस्था करने के लिये क्या निकट भविष्य में शिक्षा मन्त्रियों का कोई सम्मेलन आप करेंगे जिसमें व्यापक रूप से इस पर विचार कर सकें? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि अभी तक जो असमानता दिखाई दे रही है उसे तत्काल दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाया जा रहा है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी शिक्षा अभी प्रान्तीय विषय है और इसलिये हम प्रान्तों से बात कर रहे हैं। इसके लिये मैंने 10, 11 अगस्त को प्रान्त के शिक्षा मन्त्रियों की मीटिंग बुलायी है जिसमें यह सवाल उठेगा। यह सही है कि कहीं कहीं अभी संख्या कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगहों में उतनी कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आयेगी तो मैं प्रान्त के शिक्षा मन्त्री के पास भेज दूंगा।

SHRI V. ARUNACHALAM: I would like to know from the hon. Minister whether this Government will introduce the regional languages of the respective States as the medium of instruction in the Colleges and Universities which are under the control of the Central Government.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The Regional language has not been defined in our Constitution. There was a national policy on education and in that national policy on education which was adopted by this House it was provided that regional languages were already in use as media of instruction at primary and secondary stages. Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the University stage. So the difficulty is that there is no clear cut definition of Regional language. In addition to that there are also certain linguistic minority groups in particular region. Their cases will have to be considered. So, it is very difficult on my part to say when it

will be possible to introduce Regional languages in all the institutions controlled by the Central Government.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह पहले से तय है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक किन-किन विश्वविद्यालयों ने केन्द्र के आदेश का पालन नहीं किया है, उनके नाम क्या हैं।

यह बात सत्य है कि क्षेत्रीय भाषाओं का जिस प्रकार से पूर्णतः अध्ययन कराना चाहिए वह नहीं हो पाता है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षक न मिलते हों, पढ़ाने के लिये पुस्तकें न मिलती हों या और कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें तेज गति आये, अधिक स्कूलों में लोग क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ें, उनके लिये कौनसी व्यवस्था वह करने जा रहे हैं

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं वह फहरिस्त पढ़ देता हूं, जहां अभी तक विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी चल रही है :—

1. आन्ध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
2. आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
3. बरहामपुर यूनिवर्सिटी,
4. विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
5. हैदराबाद यूनिवर्सिटी,
6. जवाहरलाल नेहरू टैक्नालाजी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद,
7. कोंकण कृषि विद्यापीठ,
8. नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग,
9. उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नालाजी,
10. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
11. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,
12. रुड़की यूनिवर्सिटी,
13. तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
14. यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलौर,
15. उत्कल यूनिवर्सिटी,

और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं हैं:—

1. बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी एण्ड साइंसेज, पिलानी,
2. सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ लैंग्वेजेज एण्ड फारेन लैंग्वेजेज, हैदराबाद,
3. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली,
4. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज, बंगलौर,
5. इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद,
6. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, बम्बई।

मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया, जबर्दस्ती हम कर नहीं पाते हैं।

SHRI HITENDRA DESAI: The reply is vague. They say that they are using one or more Regional languages as a media of instruction for specific courses. Which are the universities which have switched over to the regional language as a medium of instruction in all courses?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I did not get the full answer for that because the University Grants Commission collected the information. The position prevailing on 1st July, 1977 has been stated by me. It is not

possible for me to say whether they are being used in all courses. There are some science courses. English will be taught in Englih medium.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्षेत्रीय भाषा के बारे में सवाल पूछा गया है और मन्त्री जी को जानकारी नहीं है । मूल सवाल तो वही है कि किन-किन विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा पढ़ायी जाती है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : किन-किन विश्वविद्यालयों में यह है यह तो फहरिस्त में है लेकिन वह जानना चाहते हैं किन किन भाषाओं में पढ़ाई होती है यह नहीं है ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: How many universities have introduced regional languages as medium of instruction in technical education and in medical colleges? Has Government any proposal to introduce regional languages in technical and medical education?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: From the list of universities I have just now read out where instruction is given through English it will be found that mostly they are technical universities or agricultural universities. Text books are being printed for science subjects. As long as they are not completed it will not be possible to introduce regional language in scientific institutions and institutions which give instruction in technical matters. The UGC prepared in 1970-71 a programme for providing for support for writing quality text books at university level in order to promote Indian authorship of quality books. Upto April 1977 a total of 373 projects were approved. Of these manuscripts are completed in 82 cases. 85 were withdrawn. The remaining 233 are in progress. So, attempts are being made in this direction.

श्री जनेश्वर मिश्र : मन्त्री जी ने अभी बताया है कि क्षेत्रीय भाषा की निश्चित परिभाषा नहीं बन पायी है । मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय भाषा शब्द देश की एकता के लिए खतरनाक भी है इसलिए मैं मातृभाषा शब्द इस्तेमाल करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या कोई भी छात्र प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक अगर मातृभाषा में पढ़ना चाहे तो शिक्षा विभाग उस को पढ़ाई की सुविधा देने के लिए तैयार है और क्या उसके लिए वह राज्य सरकारों को इस दिशा में निर्देश देगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हमारा जो कांस्टीट्युशन है उसकी धारा 350 (क) में यह है—

Facilities for instruction in mother tongue at the primary stage are to be provided. The question is whether it should be done at university level. Instruction is being given in mother tongue in some of the places. As regards minorities there is a special constitutional provision under Article 29 and 30. They get special protection. Linguistic minority gets protection under that provision.

SHRI VASANT SATHE: Wherever efforts were taken to impart education in all subjects in regional languages as was done in Maharashtra and Madhya Pradesh it was found that the students not only suffered because the interviews were in English in All India Services but they were found deficient because the medium of instruction was regional language. Have you considered the factor of not ruining the lives of these students and allowing interviews in regional languages for these students? What is your policy?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: This is an important question and this aspect of the matter was considered by the Kothari Commission in 1966. The Education Commission has stated:

"So long as the prized post in the administration goes to the students who have a good command over the

English language, it will not be surprising if a substantial portion of students continue to prefer education given through it."

That was the finding of Kothari Commission and, we find that this matter relating to language for services does not come within the competence of my Ministry; it goes to the Home Ministry.

SHRI VASANT SATHE: How are you coordinating this because the students are going to the Convent schools? What is your policy?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Mr. Speaker, Sir, if the suggestion of Mr. Sathe is accepted that all-India Services Examination will be held in regional languages, then India will only be divided.

MR. SPEAKER: You will please ask your question.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I am putting my question. Sir, I want to know from the hon. Minister in how many colleges and universities, the medium of instruction is Hindi? I also want to know from him whether he is thinking of opening at least one Hindi University in each State and, if not university, at least one Hindi College in each State?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, regarding this, there is a three language formula which has been recommended and, as I have been repeating every time instruction upto a certain stage is entirely the State subject and we cannot impose our decisions. This is the position. But as I have explained earlier also, the Central Government is trying to encourage the study of Hindi and provide funds for developing Hindi. Also the U.G.C. is trying to have instructions through Hindi in different institutions. There is no proposal to open any University on the line Shri Reddy has suggested.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : क्या केन्द्रीय विद्यालयों में थ्री-लैंग्वेज फ़ार्मूला के मुताबिक पढ़ाई हो रही है; यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: This question does not arise because this question does not concern the University.

श्री रसीद मसूद : क्या किसी यूनिवर्सिटी में उर्दू को मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन बनाने का सरकार का विचार है ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Urdu is being taught in many universities and there are some special Universities like the Aligarh Muslim University, Jamia Milia Islamia, etc., where Urdu is being taught as one of the major languages and is the medium.

श्री रसीद मसूद : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है ।

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Speaker, Sir, everybody is trying to beat about the bush because this is a very important question. A number of universities in Hindi States have not recognised the Southern—regional—languages to be the medium of instruction nor have they encouraged them in the various universities here even as a language.

You have allowed only one language in the Hindi speaking States. In non-Hindi States, you are imposing, three or four languages. Why is there such a discrimination? I want to know whether the U.G.C. has issued any instructions that the regional languages of the Southern States should be compulsorily introduced in the Northern Hindi Universities? I want to know the reactions of the Government in this regard. Otherwise, there will be a strong reaction if there is any imposition of Hindi on the Southern States.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The question is not clear.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek your protection. He is not answering. (*Interruptions*)

DR. PRAPAT CHANDRA CHUNDER: Sir, the question was relating to medium of instructions through regional languages. It has nothing to do with non-regional language. (*Interruptions*).

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek your protection. I seek the protection of the Chair. The government is evading to answer my question. They have no language policy. (*Interruptions*).

चौधरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हुई थी कि मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन जो हैं वह विश्वविद्यालय थोप नहीं सकते ? उस फ़ैसले के बाद क्या सरकार कदम उठाएगी कि जो रीजनल लैंगुएज हैं, उनको यूनिवर्सिटियां लागू करें ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : उच्चतम न्यायालय ने जो राय दी थी, वह राय डी० ए० वी० कालेज, भटिण्डा **बनाम** पंजाब यूनिवर्सिटी एण्ड अदर्स, रिट पेटिशन्स नं० 353 और 354 आफ़ 1970 में दी थी और उसमें संविधान की धारा 29 और 30 पर बहस चली थी । उसके बाद न्यायालय ने यह कहा था कि मातृ-भाषा के अलावा और कोई दूसरी भाषा अल्प समुदाय पर जोर जबर्दस्ती लागू नहीं की जा सकती ।

गुजरात में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

*606. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सिंचाई के मामले में पीछे है;

(ख) यह बात सुनिश्चित कराने के लिये कि राज्य सिंचाई के मामले में पिछड़ा न रहे केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) गुजरात में कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जाने की सम्भावना है और कब तक ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) 19 per cent of the total cropped area in the State of Gujarat has been provided with irrigation facilities as compared to the national average of about 28 per cent.

(b) The State Government have taken up a number of major, medium and minor irrigation schemes and the financial allocation for irrigation programme is being raised from plan to plan. Major rivers of the State except the Narmada have been generally harnessed and groundwater exploitation is stepped up on a scientific basis.

(c) The State Government have assessed that in the ultimate stage when all technically and economically feasible schemes (excluding Narmada) are completed, the total irrigation potential of 2.64 million hectares will be created. An additional potential for about 0.12 million hectares would also be available from the four new projects of Gujarat in Narmada basin, agreement in respect of which was reached in March, 1975 in a meeting between the four States with assistance of the Government of India, pending the Tribunal's decision and without prejudice to their claims before the Tribunal. Subject to availability of funds these schemes (including above 4 schemes of Narmada basin but excluding other schemes of this basin) will be completed by the end of the Seventh Five Year Plan.